

Mizoram	389.66
Nagaland	304.99
Tripura	11.50
TOTAL	2141.38

Entry of M/s. Nestle India Ltd. in ice cream business

3835. SHRI SUNDER SINGH BHANDARI: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether Government are aware that Nestle India Ltd., a multinational Company is preparing to enter in ice cream business;

(b) whether Government are aware that Nestle has already set up more than 200 chilling centres in the country; and

(c) if so, Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI DILIP KUMAR RAY):

(a) to (c) This Ministry is not aware about any plant of M/s. Nestle India Ltd. for entering into ice cream business/ or setting up of chilling centres. In accordance with the Ministry of Industries's Notification No. S.O. 298 (E) dated 3.4.1997, manufacture of ice cream has been dereserved from Small Scale Sector, and hence any company is now free to manufacture ice cream without any industrial licence under I (D&R) Act, 1951.

Reduction in Taxes on the Processed Foods

3836. SHRI AKHILESH DAS: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item published in the Times of India dated 18th March, 1997 under the caption "Indian food processing industry at cross roads";

(b) if so, Government's reaction thereto;

(c) whether the heavy taxation on these processed food has made them highly expensive and also out of reach for the middle class households; and

(d) the measure Government propose to take to ensure reduction in taxes on the processed food?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRY (SHRI DILIP KUMAR RAY): (a) Yes, Sir,

(b) to (d) Processed food industry has been growing steadily over the last few years. Undoubtedly levying of tax on a product would make it more expensive. However, Govt. has been taking various measures including fiscal concessions for promotion of this sector.

Processing of Fruits and vegetables in the country

3837. SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) the quantity of fruits and vegetables produced in the country and the percentages thereof which is being processed;

(b) the shortcomings in the proper growth of the industry; and

(c) the steps proposed to be taken to encourage modernisation of food processing industry as it has failed to register the desired level of growth despite the country being the world's largest producer of fruits and vegetables?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRY (SHRI DILIP KUMAR RAY): (a) Production of fruit and vegetables in the country is estimated to be around 100 million tonnes. Processing of fruits and vegetables has increased from 0.5% in 1988 to 1.8% in 1996 of the total production.

(b) and (c) While there is a great potential for growth of the industry, the slow growth can be attributed to factors such as lack of post harvest processing infrastructure, inadequate linkage between the farmers and the processors, and lack of marketing efforts etc. Government has been talking various steps for development of the Food Processing Industries including fruit and vegetable processing, which inter-alia includes liberalised policies for investment, including foreign investment, removal of restrictions thereon, providing fiscal concessions. Ministry of Food Processing

Industries is also implementing various Plan Schemes under which financial assistance is provided to State Governments/Joint Sector/Cooperative Sector etc.

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए प्रोत्साहन योजना

3838. श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिपुरा सहित सभी राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में अवसंरचनात्मक विकास कम होने के कारण इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए कोई प्रोत्साहन योजना नहीं बनाई गई है;

(ख) क्या इस स्थिति के परिणामस्वरूप निजी निवेशकों द्वारा निवेश नहीं किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस क्षेत्र में निजी निवेशकों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इस संबंध में वर्ष 1996-97 के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय): (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने देश भर में इसमें त्रिपुरा शामिल है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के समग्र विकास के लिए आठवीं योजना के दौरान अनेक विकासोन्मुख योजना स्कीमों बनाई और लागू की हैं। नौवीं योजना अवधि के दौरान भी ऐसी स्कीमों को लागू करने का प्रस्ताव है। ये स्कीमें परियोजना विशेष हैं न कि राज्य विशेष।

जुलाई, 1991 से अब तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में औद्योगिक उद्यमों ज्ञापनों और अनुमोदनों के माफ़्त लगभग 7700 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश समेत मुख्यतः निजी क्षेत्र द्वारा 63200 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। इन परियोजनाओं में से 10,000 करोड़ रुपये से अधिक पूंजी निवेश की परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा चुका है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वयं किसी राज्य में खाद्य प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना नहीं करता। योजना स्कीमों के तहत खाद्य प्रसंस्करण के विकास के लिए केन्द्र/राज्य सरकार के संगठनों, संयुक्त क्षेत्र/सहायता प्राप्त परियोजनाओं, स्वयंसेवी एजेंसियों, सहकारिताओं, निजी उद्यमियों आदि को वित्तीय सहायता दी जाती है। 1996-97 के दौरान हमारी स्कीमों के लिए परिव्यय 40 करोड़ रुपये था।

मध्य प्रदेश में आम प्रसंस्करण उद्योगों को वित्तीय सहायता दिया जाना

3839. श्री अजीत जोगी: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मध्य प्रदेश में आम प्रसंस्करण उद्योगों को कोई वित्तीय सहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ परियोजनाएँ स्वीकृति हेतु सरकार के विचाराधीन हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय): (क) और (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मध्य प्रदेश समेत देश में फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों, इसमें आम प्रसंस्करण उद्योग शामिल है, की स्थापना/विस्तार/उन्हें बेहतर बनाने के वास्ते सहायता उपलब्ध कराने हेतु फल तथा सब्जी, प्रसंस्करण के क्षेत्र में अनेक विकास योजना स्कीमों चला रहा है। ये स्कीमें राज्य विशेष नहीं होतीं। वैसे मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा खादी तथा ग्रामोद्योग को बढ़ावा दिया जाना

3840. श्री एसएनएस अहलुवालिया: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने खादी तथा ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने हेतु कोई विशेष योजना तैयार की है और उसे लागू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बिहार में ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने में आयोग की अब तक क्या भूमिका रही है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) बिहार राज्य सहित पूरे देशभर में यथासंभव अधिकाधिक जीव्यक्षम खादी तथा ग्रामोद्योग एककों को बढ़ावा देने की खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की कोशिश रही है। उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के अनुसार 2002 ई० सन् के अन्त तक के बी आई क्षेत्र में 5.6 मिलियन व्यक्तियों को रोजगार सृजित करने के लिए खादी तथा